दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 16 नवम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 49

महत्वपूर्ण एवं खास

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, शिवकुमार को मिली राहत

नईदिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही ईडी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट से डीके शिवकुमार को मिली जमानत को चैलेंज किया गया था। आपको बताते जाए कि डीके शिवकुमार मनी लाउंड्रिंग मामले में जमानत पर जेल से बाहर हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अपने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ने के लिए कहें। कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि आप डीके शिवकुमार केस में पी चिदंबरम की दलील पेश कर रहे हैं, जो कि कॉपी-पेस्ट है और इसमें बदलाव भी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत को चुनौती देने के बाद उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार की याचिका पर ईडी को नोटिस दिया कि वह उनके खिलाफ एफआईआर को खारिज करें।

झारखंड प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छुएः मोदी

» प्रधानमंत्री ने स्थापना दिवस पर बधाई दी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा झारखंड की जनता को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छुए और भगवान बिरसा मुंडा के समृद्ध, सशक्त और खुशहाल राज्य के सपने को साकार करे। झारखंड शौर्य और करुणा का पर्याय है। इस राज्य के लोग हमेशा प्राकृति के साथ सामंजस्य से रहते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

ऑड-ईवन पर सोमवार को अंतिम फैसलाःकेजरीवाल

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वे जबरन दिल्ली वासियों पर ऑड-ईवन थोपना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि अगले दो दिनों में हवा कुछ साफ होने के आसार हैं, ऐसे में वह जबरन दिल्ली वासियों पर ऑड-ईवन थोपना नहीं चाहते हैं। अगर अगले दो दिनों में स्थिति नहीं सुधरी तो सोमवार को ऑड-ईवन बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। आज दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम खत्म हो रहा है। आपको बताते जाए कि देश की राजधानी दिल्ली में आज भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।एयर चालिटी इंडेक्स ने मंदिर मार्ग इलाके में 700 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। द्वारका, पूसा रोड, सत्यवती कॉलेज, पंजाबी बाग में यह 700 तक पहुंच चुका है।

इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को स्वदेश लाएं यूरोपीय देशः अमेरिका

वॉशिंगटन। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा है कि वे इराक एवं सीरिया में हिरासत में बंद इस्लामिक स्टेट के उन आतंकवादियों को अपने देश में वापस लेकर उनके खिलाफ अभियोग चलाएं जो उनके देश के नागरिक हैं। पोम्पिओ ने करीब 30 गठबंधन सदस्यों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि यह आवश्यक है कि वे दोनों देशों में आईएस के कब्जे के समय किए गए अत्याचारों के लिए हिरासत में बंद हजारों विदेशी आतंकवादियों को जवाबदेह बनाएं। हिरासत में बंद कई विदेशी आतंकवादी यूरोप से हैं, लेकिन उनके देश उन्हें वापस लेने के इच्छुक नहीं है और अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इस मामले में गठबंधन साझीदारों के बीच अब भी मतभेद है कि इन आतंकवादियों से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हैं।

राजनाथ ने दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ने वाले सिसेरी पुल का किया उद्घाटन

» रक्षा मंत्री ने पूर्वोत्तर में सीमा अवसंरचना को उन्नत बनाने का आह्वान किया

ईटानगर (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सीमा अवसंरचना को उन्नत बनाने का आह्वान किया। वे आज अरूणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन कर रहे थे। यह 200 मीटर लंबा पुल जोनाई-पासीघाट-राणाघाट-रोइंग सड़क के बीच बना है, जो दिबांग घाटी और सियांग को जोड़ेगा। उल्लेखनीय है कि अरूणाचल प्रदेश के लोग बहुत पहले से इसकी मांग कर रहे थे। इस पुल के बन जाने से पासीघाट से रोइंग जाने के सफर में लगभग पांच घंटे की कमी आएगी।

रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास रहने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर तथा पूरे देश की सुरक्षा के लिए अवसंरचना को उन्नत बनाना बहुत आवश्यक है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने राज्य में कई अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख किया, जिनमें भालुकपोंग-टेंगा-तवांग के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन, पासीघाट हवाई अड्डे को शुरू करना, होलोंगी हवाई अड्डे और सेला दर्रे पर सुरंग निर्माण की स्वीकृति आदि शामिल हैं। क्षेत्र में सड़क, रेल, हवाई मार्ग, जलमार्ग और डिजिटल नेटवर्क की मजबूत श्रृंखला शुरू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) से बाहर रहने का निर्णय किया है, ताकि देश के आर्थिक हितों और खासतौर से पूर्वोत्तर के हितों की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा, 'आप सबने देखा होगा कि बैंकॉक में हाल में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि भारत आरसीईपी का हिस्सा नहीं होगा। यदि भारत आरसीईपी में शामिल हो जाता तो किसानों, मजदूरों, कारखानों और उद्योगों पर बहुत प्रभाव पड़ता। यह एक बड़ा निर्णय है।'

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल का अंतिम दिन

नईदिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का आज अंतिम कार्य दिवस है। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन चीफ जस्टिस गोगोई कुछ ही देर के लिए अपने कार्यालय में बैठे। परंपरा के अनुसार सीजेआई गोगोई अपने उत्तराधिकारी जस्टिस एस. ए. बोबडे के साथ कोर्ट रूम में बैठे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ तीन मिनट में दस मुकदमों में नोटिस जारी कर दिया। 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल का अंतिम दिन है, लेकिन इस वक्त वीकेंड पड़ रहा है।

चीफ जस्टिस गोगोई से इस दौरान कुछ पत्रकारों ने इंटरव्यू की अपील की, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बात करने से मना कर दिया। बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित फेयरवेल फंक्शन में भी सीजेआई संबोधन नहीं देंगे।

इससे पहले चीफ जस्टिस गोगोई साढ़े 10 बजे कोर्टरूम पहुंचे, तो कमरा पूरी तरह से भरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश खन्ना ने सभी की तरफ से जस्टिस गोगोई का धन्यवाद किया और शुभकामनाएं दीं।

शीतकालीन सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने 17 को बुलाई सर्वदलीय बैठक

नईदिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा अध्यक्ष ने 17 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 17 नवम्बर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि 18 नवम्बर को शीत कालीन सत्र प्रारंभ होगा। आपको बताते जाए कि शीतकालीन सत्र में अर्थव्यवस्था में मंदी , महाराष्ट्र के घटनाक्रम और जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने और किसानों के मुद्दे पर विपक्षी दलों के कड़े तेवरों को देखते हुए आगामी शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है और इसे सुचारू ढंग से चलाना सरकार के लिए टेढी खीर साबित होगा। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और 13 दिसम्बर तक चलेगा। मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद यह संसद का दूसरा सत्र होगा। जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने और इसका दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजन किए जाने के बाद भी संसद का सत्र पहली बार बुलाया गया है। सरकार ने इससे संबंधित विधेयक सत्र के अंतिम दिनों में पारित कराए थे और विपक्ष विरोध के बावजूद इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में विफल रहा था।

22 करोड़ के फर्जी जीएसटी चालान जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

नईदिल्ली (आरएनएस)। सेन्ट्रल जीएसटी दिल्ली नॉर्थ की कमिशनरी ने वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान जारी करने के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में नवीन मुटरेजा और केशवराम को गिरफ्तार किया गया है और पटियाला हाऊस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी 42 फर्जी कंपनियां चला रहे थे, जो धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आगे बढ़ाने का काम करती थी,

जिसके कारण सरकारी खजाने को धोखे से लूटा जा रहा था। प्रथम दृष्ट्या धोखाधड़ी से करीब 22 करोड़ रुपये के चालान काटे गये, जिसमें 150 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी।

दोनों आरोपी अन्य बातों के अलावा दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की फर्जी कंपनियों के जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर लेते थे और इसके लिए असंदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे तथा करोल बाग, दिल्ली में एक परिसर से इन कंपनियों के वस्तु रहित चालान और ई-वे बिल तैयार करते थे। प्रारंभिक जांच के बाद पता चला कि अनियमित कंपनियों की आतंरिक और बाहरी आपूर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं था। इन कंपनियों ने अनेक खरीदारों को धोखे से आईटीसी दे दिया था, जिन्होंने बाहरी आपूर्ति के लिए अपनी जीएसटी देनदारी पूरा करने के लिए इसका लाभ उठाया।

अतः दोनों आरोपियों ने सीजीएसटी कानून, 2017 के धारा 132(1) (बी) और (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध किया, जो धारा 132(5) के अंतर्गत संज्ञेय और गैर-जमानती है तथा इस कानून की धारा 132 (1) (आई) के तहत दंडनीय है। इसके अनुसार नवीन मुटरेजा और केशवराम को 14 नवम्बर, 2019 को गिरफ्तार किया गया।

बीएमसी के ठेकेदारों के 44 ठिकानों पर आईटी के छापे

» 735 करोड़ की गड़बड़ी आई सामने

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गुरुवार को बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम के लिए काम कर रहे सिविल ठेकेदारों ने 735 करोड़ रुपए की कथित अनियमितताएं की हैं। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति-निर्माण का काम करती है। मुंबई और सूरत में 6 नवंबर को एंट्री प्रोवाइडरों और लाभार्थियों के 44 ठिकानों पर खोज और सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया था, जो मुख्य रूप से बीएमसी में सिविल अनुबंधों के काम करने में लगे हैं। बीएमसी देश के सबसे अमीर नगर निगमों में से एक है।

विभाग ने कहा कि छापे के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि, बड़े पैमाने पर कर चोरी और धन शोधन किया गया है। सूत्रों ने कहा कि कुछ बीएमसी अधिकारियों के परिसर में भी आई-टी के लोगों ने सर्वेक्षण किया। आयकर विभाग ने एक बयान में कहा, 'एंट्री प्रदाताओं और लाभार्थियों पर छापे मारे गए, जो मुख्य रूप से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के तौर काम करते हैं।' ऐसी रिपोर्टें थीं कि कुछ ठेकेदारों ने एंट्री प्रोवाइडर से ऋण आदि के रूप में एंट्री ली थी और आय को कम दिखाने के लिए खातों के पासबुक में खर्च भी बढ़ा हुआ दर्शाया था।

कर निकाय ने कहा, 'अब तक 735 करोड़ रुपये की अनियमितता का पता चला है

और आवास प्रविष्टियों की मात्रा निर्धारित की जा रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत पाए गए हैं'। निकाय ने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन में 'दूसरों के बीच ऋण या बिल के रूप में व्यवसायों को प्रविष्टियां देने के लिए फर्जी कंपनियों (एंट्री प्रोवाइडर द्वारा मंगाई गई) के उपयोग का भी पता चला है।

शिवसेना का ही होगा सीएम, 14-14-12 के फॉर्मूले पर होंगे मंत्री

» महाराष्ट्र में गठबंधन का ड्राफ्ट तैयार!

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के बीच शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सरकार बनाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। खबर है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर तीनों ही दलों के बीच एक राय बन गई है। गुरुवार को तीनों दलों ने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक ने कहा, अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके आत्मसम्मान को बनाए रखे क्योंकि उसने अपने पुराने गठबंधन को छोड़ा है। कांग्रेस सरकार का हिस्सा होगी या वह बाहर से हमारा समर्थन करेगी इसका जल्द फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद मिल गया है जबकि एनसीपी को 14 और कांग्रेस को 12 मंत्रीपद दिए जाने पर फैसला किया गया है। खबर है कि शिवसेना के खाते में 14 मंत्री पद आए हैं। सरकार बनाने की गतिविधियों ने रविवार से गति पकड़नी तब शुरू की जब शरद पवार ने दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने की उम्मीद जताई। एनसीपी नेताओं के अनुसार पहले गांधी और पवार बैठक करेंगे और उसके बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है कि क्योंकि यह सरकार गठन पर आखिरी मुहर लगाने का काम करेगी।

देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने केन्द्र और राज्यों का हो संयुक्त प्रयासः रिजिजू

नईदिल्ली (आरएनएस)। राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के युवा मामलों एवं खेल मंत्रियों और सचिवों का सम्मेलन शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित किया किया गया। केन्द्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरेन रिजिजू ने देश के लोगों को स्वस्थ बनाने तथा देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र और राज्यों से संयुक्त प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवाओं का है। हमें इस शक्ति को देश के विकास में लगाने का काम करना है। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से अपनी गतिविधियों को केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों को इस मामले में एक टीम की तरह काम करना चाहिए।

रिजिजू ने कहा कि इस काम के लिए उनके मंत्रालय के पास प्रचुर मात्रा में मानव संसाधन उपलब्ध हैं, जो वित्तीय संसाधनों की कमी को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। केन्द्र द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में 80 लाख से ज्यादा वालंटियर काम कर रहे हैं। इस साल 2 अक्तूबर को 24 लाख से ज्यादा वालंटियरों ने प्लॉगिंग कार्यक्रम में भाग लिया, किसी एक कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी का बड़ा रिकार्ड है।

पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक में सात देशों ने लिया हिस्सा

नईदिल्ली (आरएनएस)। वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 14 नवम्बर को अरूणाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पाद पर पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया।

बैठक में, सात देशों भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ग्रीस के दस अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों ने हिस्सा लिया और निर्यातकों के साथ बातचीत की। उत्पादकों और निर्यातकों ने अरूणाचल प्रदेश के उत्पादों जैसे मैन्डरिन संतरा, किवी, अनानास, किंग मिर्च, बड़ी इलायची, ऑर्गेनिक उत्पादों, अन्य ताजे फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों को प्रदर्शित किया।

कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर क्षेत्र खासतौर से अरूणाचल प्रदेश से कृषि-निर्यात के लिए बाजार से सम्पर्क बढ़ाने के उद्देश्य से एपीडा और अरूणाचल प्रदेश के कृषि और बागवानी विभाग ने ईटानगर में सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। अरूणाचल प्रदेश सरकार ने एपीडा के अध्यक्ष और अरूणाचल प्रदेश सरकार के कृषि और बागवानी विभाग में सचिव बिदोल तायेंग के साथ दो

दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

यह सम्मेलन आयातकों और निर्यातकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की बी2बी और बी2जी बैठकें और कृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात के अवसरों और संभावनाओं का पता लगाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर अरूणाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसानों और उत्पादकों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

उद्घाटन सत्र के दौरान अरूणाचल प्रदेश के कृषि और बागवानी मंत्री तागे ताकी ने इस बैठक में आये प्रतिनिधियों का स्वागत किया और बताया कि क्रेता और विक्रेता बैठक खरीदारों और किसानों के बीच सम्पर्क स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की 75-80 प्रतिशत भूमि अनछुई है और इन इलाकों में अनेक कृषि फसलों को लगाया जा सकता है, क्योंकि अरूणाचल प्रदेश जलवायु के अनुसार वर्ष में पांच प्रकार की फसलें उगा सकता है।